Overtime Rates

1580. PROF. RUPCHAND PAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there was different overtime rates in different Divisions of Railway for similar or same jobs; and

(b) if so, whether Government have any proposal to introduce uniform overtime rates of payment?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). In accordance with the recommendations of the Railway Labour Tribunal, 1969, the rate of overtime of railway employees varies depending on whether the rostered hours of duty in an averaging period include the time spent on preparatory and/or complementary work or not. As such the question of introducing uniform rates of overtime payment does not arise.

राजस्थान में छठी योजना के दौरान रेल लाइनों की लम्बाई

1581. **श्री अशोक गहलोत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने का विचार है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान, क्षेत्रवार, सरकार द्वारा राजस्थान में कितने किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने का विचार है ; और

(ग) यदि राजस्थान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी योजना के प्रारम्भ से ही 1384 कि० मी० लम्बी रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है । 1980–81 के दौरान 4 और नई लाइनों को जिनकी लम्बाई 285 कि० मी० है, निर्माण के लिए अनुमोदित कर दिया गया है । इनमें से 257 कि० मी० लम्बी लाइनों को यातायात के लिए पहले ही खोला जा चुका है और 98 कि० मी० लम्बी नई लाइनें तैयार है और आशा की जाती है कि इन्हें 31 मार्च, 1981 तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा । 1981–82 के दौरान 8.31 कि० मी० लम्बी बड़ी लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव है । छठी योजना के दौरान 230 कि० मी० लम्बी अतिरिक्त नई बड़ी लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). कोटा-चित्तौड़गढ़–नीमच बड़ी लाइन के निर्माण को 41.09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 1980–81 के बजट में शामिल कर लिया गया है । 1981–82 में इस कार्य के लिए 2.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

डी० ई० एन० (कोन्स) द्वारा कर्मचारियों को ओपन लाइन का सौंपा जाना

1582. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० ई० एन० (कोन्स) पूर्व रेलवे लाइन धनबाद द्वारा 1965 के बाद जो परिसम्पत्तियां विशेष रूप से निर्मित अंग आदि (वर्क्स पोर्शन) सृजित हुई और 'ओपन लाइन' को सौंपी गई उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) डी० ई० एन० (कोन्स) धनबाद के कितने कर्मचारी परिसम्पत्तिय के रूप में 'ओपन लाइन' को सौंपे गये ;

(ग) 'ओपन लाइन' को ऐसे कर्मचारियों को सौंपने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :
(क) विवरण इस प्रकार है :

1. रेलपथ :

(i) गोमी, बन्दपुरा डांहरी लाइन दुगदा चरण-I और II

(ii) फुलवारत्तानर-जमुनियातनगर लाइन का दोहरीकरण

(iii) पतरातु और बेरमी के मध्य मुख्य यार्ड में रेलपथ कार्य

(iv) बरकाना-परिहार लाइन ।

2. निर्माण कार्य

(i) सुंदानडीह और धनबाद के बीच पाइप लाइन

(ii) जागेश्वर बिहार और दुनरी के बीच अनुरक्षण कार्य

(iii) पतरातू और बेरमी के बीच भिन्न-भिन्न निर्माण कार्य ।

(ख) चालू लाइन को दी गई परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में रेलपथ के लिए 329 कर्मचारी और निर्माण कार्यों के लिए 30 कर्मचारी मण्डल इंजीनियर, धनबाद को दिये गये थे ।

(ग) सामान्य नियमों के अनुसार परिसम्पत्तियों के सृजन के बाद रेलवे के निर्माण और चालू लाइन संगठनों के बीच अनुरक्षण-पदों के सृजन के प्रस्ताव के बारे में वित्त विभाग की सहमति से संयुक्त रूप से विनिश्चय किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कोराला जयंत रेल लाइन

1583. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोराला जयंत रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने अभी तक राज्य सरकार को किसानों को वितरण के लिए मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) चरण 1 केरायला रोड से काकरी तक 33.05 कि0 मी0 की कुल लम्बाई में से 21.43 कि० मी० की लाइन को 30–6–1981 तक खोले जाने की आशा है ।

चरण 2—काकरी से जयन्त (अर्थात् शेष 11.62 कि0 मी0) को खोले जाने की लक्ष्य तिथि 31–3–1982 है बशर्ते कि 31–3–1981 तक उ० प्र० सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि को खाली कब्जा दिला दिया जाये ?

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।